(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों और कितने राजनेताओं को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है;

(ग) अभी तक अध्यक्ष के कितने पद रिक्त हैं; और

(घ) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के नामों की सूची संलग्न है। (देखिए परिशिष्ट 157, अनुपत्र संख्या –19)

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 कार्यरत अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। किसी भी राजनीतिज्ञ को इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर दिनांक 31–1–1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक) के 45 पद रिक्त पड़े हैं।

(घ) रिक्तियों को भरना एक सतत् प्रक्रिया है और पदावधि की समाप्ति त्यागपत्र, बाद में किसी और कार्यालय में चले जाने इत्यादि कारणों से किसी भी समय कुछ पद रिक्त हो सकते हैं। सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त पदों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वरीयता के आधार पर भरने के लिए गठित प्रयास किए जाते हैं।

Concessions for small scale industries

811. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have not so far issued any Notification or formal orders giving effect to the various concessions given to small scale industry in the Industrial Policy announced during the last year, with the result that the benefit thereof has not reached the proper quarters;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether necessary orders to implement the provisions of the above Policy regarding the small scale industries' promotion and development will be issued now; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): (a) to (d) The paper on "Policy Measures for the Promotion of Small Scale and Agro-based Industries and Changes in Procedures for Industrial Approvals" laid on the Table of Rajya Sabha on 31st May, 1990, inter-alia, contained proposal for enhancement of investment limit from the present Rs. 35 lakhs to Rs. 60 Lakhs for Small Scale Industrial units and from Rs. 45 lakhs to Rs. 75 lakhs for Ancillary units. These proposals are presently under the consideration of the Government and are likely to be finalised soon.

Assets of Large Industrial Houses

812. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of the assets of all the large Industrial Houses in the country; including their turnover; profit loss before tax deduction, as on date;

(b) whether it is a fact that in certain cases there had been a phenomenal rise in the holding of some of these industrial houses; if so, what are the details thereof and the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to check the concentration of economic power in a few industrial houses?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI